POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–1 JAN 2025 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।

email id: vote1957@gmail.com

दक्षिण कोरिया में भयंकर प्लेन दुर्घटना

प्लेन में सवार दो को छोड़कर सभी यात्री तथा क्रू के लोग काल कवलित हो गए। विमान में181 लोग सवार थे तथा मरने वालों की संख्या 179 बताई जा रही है।

प्लेन उतर रहा था। रन वे से टकराकर एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया तथा मिनिटों में आग के लपटों बदल गया।

इस तरह की भयंकर घटना वर्षों बाद सुनने को मिल रही है।

केरल में प्रेस की आजादी पर प्रहार

मलयालम दैनिक समाचार पत्र "मध्यमम" के संपादक तथा इसके एक रिपोर्टर को केरल पुलिस ने नोटिस दिया है कि उन्हें केरल राज्य लोक सेवा आयोग (KPSC) के पास नौकरी के लिए आवेदन करने वालों का डेटा कैसे मिला ! रिपोर्टर से उसकी मोबाइल मांगी गई है ताकि वे सोर्स पता कर सकें।

ज्ञातव्य है कि पत्रकारों को सोर्स बताने के लिए मजबूर करना अनुचित तथा अलोकतांत्रिक होता है तथा इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला मन जाता है। इसलिए केरल के वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने विरोध राज्य तथा जिला पुलिस मुख्यालयों तक विरोध मैच करने का फैसला लिया है ।

केरला सरकार को तुरंत मध्यस्थता करनी चाहिए वरना वाम सरकार की छवि धूमिल होगी !

नए साल 2025 की सबको हार्दिक शुभकामना

HAPPY NEW YEAR 2025 TO ALL

संसद के पास एक युवक द्वारा आत्मदाह के प्रयास

यूपी के बाघपत के पुलिसिया निष्क्रियता से परेशान एक युवक ने संसद भवन के करीब आत्मदाह करने की कोशिश की। 90% जल गया है। हॉस्पिटल में इलाज च रहा है।

युवक के कपड़ों से मिले कागजातों से पता चलता है कि इस युवक के खिलाफ बागपत में तीन मामले हैं तथा उस युवक के अनुसार पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है।

मंदिर मस्जिद विवादों पर रोक

पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिक वैधता की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए तथा पुराने विवादों पर अंतरिम रोक लगाई !

मतलब :-

1.मस्जिद मंदिर के नए विवादों पर रोक!

2.पुराने विवादों में कोई अंतरिम या अंतिम निर्णय पर रोक !

3.मस्जिदों के सर्वेक्षणों पर रोक !

अपेक्षा की जानी चाहिए कि इस तरह के विवादों का अंत होगा। यही उद्देश्य था पूजा स्थल अधिनियम 1991 का !

पर कानूनों की अदालती चुनौती के दौरान बारीकियों से बाल का खाल निकाला जाता है। जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी से विवाद बढ़ने लगे थे ।

जस्टिस मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र में जज बने

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर की नियुक्ति बतौर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में की।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस करो की मांग !

बांग्लादेश ने भारत सरकार से विधिवत मांग की है कि सत्ताच्युत तथा बांग्लादेश से भाग कर भारत में शरण लिए हुए वहां की पूर्व प्रधानमंत्री को बांग्लादेश वापस भेजा जाय।

जाहिर है इस मांग से भारत की स्थिति असहज होगी तथा भारत को इस असहजता से उबरने का कोई राजनयिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा !

Former PM And Pioneer Of Liberalisation In India Dr Manmohan Singh Is No More

I express my heartiest tribute to this learned legendary figure – a former RBI Governor, a former FM and a former PM for two consecutive terms from 2004 to 2014. He as a PM is credited with carrying on successfully alliance governments UPA-1 And UPA-2 comprising of almost all non-NDA political parties with full stability for ten years by taking all into confidence.

As Finance Minister under the Prime Ministership of Narsimha Rao he piloted the liberalisation policy in 1991.

कानून का मजाक

लोकसभा में नेता विपक्ष के खिलाफ इतनी धाराओं में मुकदमा का दर्ज कराया जाना तथा दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया जाना साबित करता है कि पुलिस किसी के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज कर सकती है!

जब भारत के संसद के नेता विपक्ष के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी किस खेत की मूली है !

गनीमत है कि दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश (Attempt to murder) वाली धारा नहीं लगाया जबकि शिकायतकर्ता ऐसा चाहते थे।

ज्ञातव्य है कि शिकायतकर्ताओं में "गोली मारो ..... को" जैसा नारा लगाने वाले ख्याति के जानेमाने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी हैं !

2001 में संसद पर हमले के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। उसी संसद के परिसर में नेता विपक्ष पर इतने सारे आरोप लगे । संसद के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे ! संसद के मुख्य द्वारा मकर द्वार जहां ये घटना हुई है

वहां की सीसीटीवी सबकुछ बयान कर सकती है पर उसका अतापता नहीं है !अगर सीसीटीवी में कोई सबूत होता तो सीसीटीवी फुटेज कब का वायरल हो गया होता!

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन, विपक्ष की सहमति के बिना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्रा का सेवाकाल समाप्त होने के बाद नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामसुब्रमणियन की नियुक्ति की गई है ।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष के चयन के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा के विपक्ष के नेता का भी समावेश है।

यहां कांग्रेस का कहना है कि अध्यक्ष के चयन में संख्या के बल पर गुणों को नजरअंदाज किया गया है । कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज जस्टिस एफ एन रोहिंटन तथा जस्टिस के एम जोसफ तथा आयोग के सदस्य पदों के लिए जस्टिस एस मुरलीधर तथा जस्टिस अकील कुरेशी के नामों की सिफारिश की थी। पर कांग्रेस के मुताबिक इनकी सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया तथा अधिक का चयन कमिटी की संख्या बल के आधार पर कर लिया गया क्योंकि समिति में सरकारी पक्ष का बाहुल्य है।

मेरा मानना है कि इस आयोग के साथ साथ सीबीआई के डायरेक्टर, चुनाव आयोग के आयुक्तों, सीवीसी के अध्यक्ष के चुनाव बहुमत से नहीं सर्वसम्मति से होने चाहिए। वरना इन निष्पक्ष पदों पर उंगली उठती रहेंगी।

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–1 JAN 2025 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

Why One Nation One Election Is Not Good !

Initially India had the system of one election only for parliamentary as we as assembly elections. First two elections were held simultaneously.

The proponents of this new-found love for ONE NATION ONE ELECTION forget the reasons as to how the elections started to be held on different dates.

It is because of split verdicts in elections where no party gets majority. This made governments unstable and necessitated mid-term polls.

Second reason is defections engineered or natural . This also caused governments to fall necessitating mid term elections.

Answer my query:-

Supposing both the elections are held simultaneously but some of the state assemblies don't get clear majority and the government formed somehow does not last long and falls within a year or two. Will you not hold assembly elections or wait till the next Loksabha elections ?

As such on the face of it the move seems to be against the federal structure of our constitution. Hence many opposition parties are opposing this.

बिहार में डायन

बिहार के चंपारण में डायन के नाम पर औरत को निर्वस्त्र कर पिटाई की घटना पर सुप्रीम कोर्ट क्षुब्ध , बिहार सरकार को भी लताड़ा

यह संविधान पर धब्बा है ! महिला की गरिमा का तार तार किया जाना वो भी इस अवैज्ञानिक बात पर की महिला डायन है शर्मनाक है।

प्रथमत: घटना का संज्ञान लेने से पुलिस का इनकार, बाद में मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट का दर्ज होना पर बाद में पटना हाइकोर्ट द्वारा जांच पर रोक लगा देना समझ के बाहर है।

बिहार सरकार द्वारा पटना हाइकोर्ट के रोक को चुनौती नहीं देना भी समझ के बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है तथा ट्रायल कोर्ट को दिन प्रतिदिन सुनवाई करने को आदेश दिया है।

घटना मार्च 2020 की है। बिहार के चमारण जिला की। 13 लोग आरोपी थे। एक औरत को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का आरोप । एक दूसरी औरत जो इस औरत को बचाने की कोशिश कर रही थी उसे भी पीटा गया। और ये सब महज इस विश्वास पर कि उक्त महिला डायन है।

प्रधानमंत्री का भाषण

संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कही गई विगत की बहुत सारी बातें , सभी नहीं, सच हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आयद आपात काल भारत के इतिहास में एक कला अध्याय के रूप में जरूर देखा जाना चाहिए। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी।

राजीव गांधी की सरकार द्वारा साहा बानो के लिए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर नकारना भी समझ के बाहर था।

पर मोदी जी द्वारा नेहरू जी के बारे में कही गई बातें सच नहीं लगती हैं।

कांग्रेस ने जो गलती की ,जनता ने उसका फल चुनावों में हरा कर दे दिया।

मोदी जी कब तक विगत की बातों को दोहरा कर अपने गलत कामों को छुपाते रहेंगे। जनता इनका भी कांग्रेस जैसा हाल कर देगी।

प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह कठिन मुद्दों को दरकिनार करते रहे। मणिपुर, संभल, बुलडोजर, नफरती भाषण, झूठे एनकाउंटर, झूठे मुठे मामलों में लोगों को वर्षों जेल में रखने की बात पर, आंदोलनों , विरोध तथा विरोधियों को कुचलने तथा यूएपीए, पीएमएलए की तहत या नक्सलवादी, माओवादी या आतंकवादी के नाम पर चुनिंदे गिरफ्तारियों पर चुप रहे।

संसद में गुंडागर्दी !

भगवान हमारे संसद को बचाएं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि संसद परिसर में ही स्वयं सांसद अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। संसद के बाहर देश की जनता मारपीट, दंगा फसाद, धक्कामुक्की, हुड़दंगबाजी (hooliganisam) देश के नियमों का हिस्सा मान चुकी है। लोकसभा तथा राज्यसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा खड़गे द्वारा शिकायत को हलके में नहीं लिया जा सकता है।

प्रश्न है कि इंडिया एलायंस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी के लोग वहां क्या कर रहे थे ? जाहिर है कि ये लोग इंडिया एलायंस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में व्यवधान यानि बाधा पैदा कर रहे थे ।

संसद के सुरक्षा बल क्या कर रहे थे ! क्या ये लोग भी तमाशा देख रहे थे !

अबतक कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती थी संसद से बाहर, अब संसद के अंदर भी हो रही है।

संसद के स्पीकर तथा अध्यक्ष तो संसद के अंदर सबका विश्वास जीतने में असफल रहे हैं। क्या संसद में असुरक्षा की माहौल को रोकने की कोशिश करेंगे !

गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली फेरीबोट का भयंकर हादसा

गेट वे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की सैर की खचाखच भरी बोट को नेवी के परीक्षण की जा रही स्पीड बोट ने जोर की टक्कर मारी। फेरीबोट के परखच्चे उड़ गए। 110 लोग फेरी बोट पर सवार थे। 13 लोगों की मरने की आशंका ।बचाव कार्य जारी !

गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा टापू पर बोट द्वारा सैर करते हुए , समुद्र का मजा लेते हुए लिए जाने वालों का तांता लगा रहता है । इस घटना ने जाहिर है घूमने फिरने वालों के मन में डर भर दिया है।

असली कारण तो जांच के बाद ही पता चलेगा। कहा जा रहा है कि नेवी का स्पीडबोट टेस्टिंग पर था, परीक्षण पर था, स्पीड का टेस्ट किया जा रहा था। इस बोट के चालकों का नियंत्रण खत्म हो गया तथा तेज रफ्तार वाला स्पीडबोट फेरीबोट से टकरा गया।

पर प्रश्न ये है कि स्पीड बोट की टेस्टिंग व्यस्त रूट में क्यों की जा रही थी !

इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग

जज साहब द्वारा विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में तथाकथित सांप्रदायिक विवादित भाषणबाजी से खफा राज्यसभा के विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने जज साहब को जज के पद से हटाने के लिए महाभियोग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर आवश्यक 50 से ज्यादा 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा सांसद तथा मशहूर वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में अन्य संसद विवेक ताखा, पी विल्सन, जॉन ब्रिटा , दिग्विजय सिंह तथा के टी तुलसी से महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उक्त भाषण के साथ साथ अन्यत्र भी दी गई विवादित जज महोदय की कुछ टिप्पणियां :-

1. देश बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा।
2. कठमुल्ला जैसे शब्द का प्रयोग
3. मुस्लिम बच्चों से दया या सहिष्णुता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि वे बचपन से ही जानवरों के कटते देखते हैं।
4. भारत को विश्वगुरू का दर्जा हिंदू ही दिल सकते हैं अन्य नहीं।
5. गाय को राष्ट्रीय जानवर घोषित किया जाना चाहिए तथा गो रक्षा को हिंदुओं का मूलभूत अधिकार घोषित करना चाहिए।
6. जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा।
7. गीता और रामायण को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
8. राम, कृष्ण, गीता , रामायण, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास के सम्मान में कानून बनाना चाहिए।

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–1 JAN 2025 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

Misgiviings about Places Of Worship Act , 1991

It is notable that the Place Of Worship Act , 1991 was passed to put an end to any relgious structures existing since prior to our Independence day ie 15th August 1947. But , of late, the new temple - mosque disputes of Gyanvapi and Sambhal and also of Ajmer Sharif are being raked up with courts taking such instances leniently. This move got futher boost after the former Chief Justice of India Justice D Y Chandrachud declared that the Act does not bar investigation to find out the nature of the structures. Lower courts and high courts are routinely allowing such petitions. This is very bad trend for our democracy !

BJP supporters of sympathisers are fed with the false narrative that the Place Of Worship Act 1991 was passed in haste by the Congress government and also that this was bad in law.

Here is how I wish to rebutt such misgivings :-

It is about 33 years since the act the Place of Worship Act was passed in 1991. After the BJP was in power from 1999 to 2004 under Vajpayee ji. Modi is there for over 10 years since 2014.

Had the act anything wrong the BJP govt could have very well corrected the same or nullified the same. But they did not do so.

So , to say that law was bad does not hold water. This is the afterthought which has gripped the mind of BJP's supporters who want to encash the Hindu Muslim division to further polarise the society on communal line.

As they have got the throne on this very issue they are searching for similar issues after Ayodhya's Ram Temple failed and people there have defeated the BJP MP from Faizabad wherein Ayodhya the seat of Ramlala is there !

अविश्वास प्रस्ताव से फ्रांस की सरकार गिरी

दुनिया के इतिहास में इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि सरकारें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा गिरा दी गई हों।

फ्रांस की नेशनल असेंबली में वाम मोर्चा NFP (New Popular Front) ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। आश्चर्यजनक तरीके से इस प्रस्ताव को वहां की अति दक्षिणपंथी पार्टी का भी समर्थन मिला। परिणामस्वरूप प्रस्ताव 577 सीटों वाली नेशनल एसेंबली में 331 मतों से पारित हो गया। वहां की मौजूदा सरकार द्वारा इस्तीफा दिया जाना तय है।

आगे किसकी सरकार बनेगी देखने लायक बात होगी। हाल में हुए वहां के नेशनल असेंबली के चुनाव में वाम मोर्चा को ज्यादा सीटें मिली थी पर बहुमत से कम थी।

जगदीशपुर में रिटायरिंग रूम्स

बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर की नगर पंचायत द्वारा एक बड़ा ही नेक काम किया गया है। इस शहर के भीड़भाड़ वाले नयकाटोला जो बिहिया पीरो स्टेट हाइवे तथा नेशनल हाइवे के क्रॉस रोड (जंक्शन) पर स्थित है में जगदीशपुर की नगर पंचायत ने एक तीन मंजिली इमारत वाला एक आश्रय स्थल बनाया है जहां लोगों के विश्राम के लिए सुविधा की सारी व्यवस्था हैं। बेड, शौचालय तथा खाने पीने की। महिलाओं तथा पुरुषों के लिए ये व्यवस्था है।

देर रात (odd hours) में फंसे (stranded) लोग इसका लाभ ले सकते हैं। खाने पीने के लिए मामूली चार्ज पर खाने पीने का भी लाभ लिया जा सकता है।

मुझे इस तरह की व्यवस्था अन्यत्र नहीं दिखता है। नगर पंचायतों ही नहीं नगर परिषदों या नगर निगमों या नगरपालिकाओं में भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है।

जगदीशपुर का नगर पंचायत सचमुच धन्यवाद का पात्र है !

“वाह ताज !” की प्रसिद्धि वाले महान कलाकार तथा तबला बादक उस्ताद जाकिर हुसेन को हार्दिक श्रद्धांजलि

बाबरी मस्जिद का फैसला न्याय का उपहास था !

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व जानेमाने जज जस्टिस आर एफ नरीमन ने अपने एक व्याख्यान में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उक्त फैसला धर्म निरपेक्षता की खुली अवहेलना है।

उनके ये बात मानी हुई है कि :-

1. बाबरी मस्जिद को गिराना भयंकर रूप से गैरकानूनी था ।
2. उस ढांचे के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था ।
3. मस्जिद 1528 में बनी थी।
4. 1858 तक मस्जिद रही।
5. 1858 से 1949 तक हिन्दू मुस्लिम दोनों प्रार्थना करते थे। मुस्लिम अंदर वाले भाग में तथा हिंदू बाहर वाले भाग में।
6. 1949 में कुछ लोगों ने ढांचे के अंदर जबरदस्ती मूर्तियां स्थापित की थी। तब से मुस्लिमों द्वारा प्रार्थना रुक गई।

इसके बावजूद इस तरह का फैसला भारत के संविधान के धर्म निरपेक्षता पर करारा चोट है !

उन्होंने बताया कि मंदिर गिराए जाने के बाद सरकारी रवैया भी ठीक नहीं रहा ! लिब्रहान आयोग गठित हुआ ।आयोग 2009 तक 17 साल सोता रहा।

मस्जिद गिराने वालों के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले में जज साहब ने सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए वर्षों बाद फैसला सुनाया जिसके तुरंत बाद उनके रिटायर होने के बाद यूपी सरकार ने उन्हें यूपी का उप लोक आयुक्त नियुक्त कर दिया !

हरिद्वार में अपहरण

घटना डबल इंजन सरकार वाले राज्य उत्तराखंड की है।मशहूर हिंदी कॉमेडियन सुनील पाल उत्तराखंड के हरिद्वार में किसी कार्यक्रम के लिए वहां जा रहे थे। हवाई अड्डा से उन्हें एक गाड़ी में पिक अप किया गया तथा बीच रास्ते एक भोजनालय के पास उन्हें उतार दिया गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए और उन्हें कार में जबरदस्ती बिठाकर एक सूनसान जगह ले जाकर 20 लाख रुपए मांगने लगे तथा धमकी देने लगे कि पैसे नहीं देने पर उनके टुकड़े टुकड़े कर के रख देंगे।

पाल ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है तथा ये कि उन्हें फोन करने दिया जाय। फोन पर उन्होंने अपने परिवार तथा दोस्तों को फोन किया। कुछ गड़बड़ी की आशंका भांपते हुए यहां मुंबई में इन लोगों ने पुलिस में शिकायत की ।

8 लाख रुपए में जान बची।

इस तरह की फिरौती वो भी दिन दहाड़े , वो भी तीर्थनगरी हरिद्वार में चिंताजनक है। भक्तों की सरकार को भी चिंता होनी चाहिए।

बेघर मुसहर/रविदास(चमार)टोली

बिहार के भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा में , आरा नगर निगम के वार्ड 14 में स्थित बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि चंदवा में मुसहर टोली तथा रविदास/चमार टोली में लोग आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कच्चे मकान जिन्हें घर कहना भी मजाक होगा।

इन्हें सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिला है।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है,
2. शौचालय नहीं है, लोग खुले में शौच करते हैं।
3. नल जल योजना नदारद है,
4. घरों में बिजली नहीं है।
5. नाली और गली पक्की नहीं।
6. गंदगी का आलम है।
7. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सात निश्चय का इन गरीबों की बस्ती में कोई अतापता नहीं है।

लोग कहते हैं कि कोई लोकप्रतिनिधि या लोकसेवक उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस्ती पूर्व कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के पैतृक घर से एकदम सटे हुए हैं। उनकी पुत्री मीरा कुमार कांग्रेस नेता हैं तथा लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं। इनका भी ध्यान इन पिछड़ों की तरफ नहीं जा पाया है।

POSTAL REG. NO. THC/251/2025-2027 RNI. REGN. NO. MAHBIL/2021/15722

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME–5 ISSUE–1 JAN 2025 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

From Twitter/X

PM Narendra Modi Mourning The Demise Of Dr Manmohan Sing the former PM

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic policy over the years. His interventions in Parliament were also insightful. As our Prime Minister, he made extensive efforts to improve people's lives.

Rahul Gandhi, LOP In Loksabha, On Dr Manmohan Singh

Manmohan Singh Ji led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation. My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family. I have lost a mentor and guide. Millions of us who admired him will remember him with the utmost pride.

अमित शाह , गृहमंत्री, भारत सरकार, पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के निधन पर

महावीर मंदिर न्यास के सचिव व पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन दुःखद है। सेवा, संस्कृति व सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित किशोर कुणाल जी ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति ।

नीतीश कुमार , मुख्यमंत्री , बिहार सरकार , पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के निधन पर

पूर्व आई॰पी॰एस॰ अधिकारी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पूर्व अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति के संस्थापक सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी का निधन दुःखद। वे एक कुशल प्रशासक एवं संवेदनशील पदाधिकारी थे। उनके निधन से प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है।

Narendra Modi, PM, India On The Demise Of Former US President Jimmy Carter

Deeply saddened by the passing of former USA President Mr. Jimmy Carter. A statesman of great vision, he worked tirelessly for global peace and harmony. His contributions to fostering strong India-U.S. ties leave a lasting legacy. My heartfelt condolences to his family, friends and the people of the US.

मलिकार्जुन खरगे , काँग्रेस अध्यक्ष , पेपर लीक तथा बिहार पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पर

BPSC अभ्यर्थियों पर बिहार की NDA सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। BPSC परीक्षा में 3.28 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती हैं तो भाजपा निर्लज्जता से इंकार करती है या युवाओं पर लाठियाँ बरसाकर उनका मुँह बंद करवाना चाहती है।

Ambarnath (in Thane District of Maharashtra) East Railway Station Area has no Public Toilets/Urinals

The Chief Officer,
Ambernath Municipal Council,
Ambernath

Dated 21/12/2024

Sub:-No Public Toilets/Urinals outside Ambernath Railway Station , Ambernath East side

Sir,

There is no toilet/urinals outside Ambernath Railway Station in Ambernath East. Consequences could well be imagined. People must be discharging/ nature's call/ urinating outside in open anywhere on available spaces.

Needless to say that this is unhygienic.

This is also against the spirit of Swachchh Bharat Mission being observed nation -wide.

The area being station area is the busiest one in terms of public traffic to and from Ambernath Railway Station. Hence the necessity for toilets/urinals could well be appreciated.

It is worth mentioning that since olden days till a few years hence - the area did have a urinal at the place beside the rickshaw stand. That was demolished a few years ago.

We were anticipating that a better facility for toilet/urinals would be made at the place. But it has not come about.

I request you kindly to see that necessary step is taken to construct a toilet/urinals at an appropriate place in the area .

This will highly relieve the people in need.

Regards
Harishankar Upadhyay
Mobile 9869435995
Editor of "The Pillars Of Democracy"

Pending Court Cases In India

Courts	Civil	Criminal	Total
Supreme Court	64536	18369	82905
High Courts	4090575	1808197	6198772
Subordinate Courts	10909404	34370337	45279741
Total	15064515	36196903	51561418

देश भर मे 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं पर किसी को है चिंता कि इस न्यायालयीन असाधारण विलंब के कारणों का पता किया जय तथा इन्हें दूर किया जय ताकि न्याय शीघ्र मिल सके ! (Courtesy : National Judicial Data Grid)

Printed, published and owned by Harishankar Upadhyay and printed and published at Flat 15B, Jeevan Jyot, Bhidewadi, Kansai Section, Ambernath (East), Dist Thane (Maharashtra), PIN 421501. Editor Harishankar Upadhyay, Mobile 9869435995